छत्तीसगढ़ की तृतीय विधान सभा
प्रथम सत्र

श्री ई.एस.एल. नरसिम्हन

राज्यपाल, छत्तीसगढ़

का

अभिभाषण

दिनांक 5 जनवरी, 2009

माननीय सदस्यगण,

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद संपन्न हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होकर पधारे आप समस्त सदस्यों को मैं बधाई देता हूं। इस अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं तथा सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

2. लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है। जागरूक मतदाताओं ने उत्साह और लगाव के साथ निर्वाचन प्रक्रिया में बढ़चढ़ कर भाग लिया है, उसके लिए सदन के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों का अभिनंदन करता हूं। संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अलग–अलग जिम्मेदारियों में लगे हजारों अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी मैं, इस सदन के माध्यम से बधाई और साधुवाद देता हूं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों से जूझकर, अथक परिश्रम से संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाया।

3. चुनाव के दौरान अपनी ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों के जवानों ने जिस तत्परता से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है, वह अपने आप में एक मिसाल है। इस दौरान नक्सलवादी हमलों में हुए शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं उनके परिवारजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं।

4. मेरी सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों पर विश्वास व्यक्त करते हुए लगातार दूसरे कार्यकाल का अवसर देने के लिए जनादेश के मायने स्वतः स्पष्ट हैं। मेरी सरकार विश्वास और समर्थन की इस पूंजी को सहेज कर रखेगी। इस विराट जिम्मेदारी के साथ जन कल्याण और विकास का सिलसिला और भी तेज गति से आगे बढ़ाने के हर संभव उपाय करेगी।

5. पांच वर्ष पहले समरसता और विकास की नई कार्य संस्कृति छत्तीसगढ़ में विकसित करने का संकल्प मेरी सरकार ने लिया था। इस संकल्प को पूरा करते हुए अपने अब–तक के काम काज से हमने छत्तीसगढ़ जैसे नवोदित राज्य के गठन का औचित्य भी सिद्ध किया है। पूरी हुई कुछ उम्मीदें अनेक नई अपेक्षाओं को जन्म देती हैं। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे।

6. मेरी सरकार विश्वास और अनुभव की पूंजी से समृद्ध हुई है। जनहितकारी विकास की गति में बढ़ोतरी और पारदर्शी, संवेदनशील प्रशासन देने का मूलमंत्र मेरी सरकार का पथ–प्रदर्शक होगा। सार्वजनिक जीवन में शुचिता को पुरजोर महत्व दिया जाएगा ताकि आदर्श नागरिता और उच्च जीवन मूल्यों की पहचान निरंतर गहरी होती जाए।

7. सर्वधर्म–समभाव और सामाजिक समरसता के ताने–बाने को मेरी सरकार ने विगत कार्यकाल में मजबूत किया है। संवेदनशील मुद्दों पर मैं चाहूंगा कि इस सदन के माध्यम से हर साल व्यापक जनहित

का कोई मसला हाथ में लिया जाए और उसे दलगत राजनीतिक नजरिए से अलग हटकर हल किया जाए। विकास और बेहतरी के लिए सकारात्मक राजनीति की यह पहल आप सभी के सहयोग से ही सफल हो सकेगी।

8. मुंबई में हाल ही में हुए आतंकी हमलों ने देश के जन–जन को झकझोर दिया है। इससे देश के कोने–कोने में आतंकवाद से लड़ने के संकल्प को एक नई मजबूती मिली है। मेरी सरकार का यह मानना है कि नक्सलवाद और आतंकवाद दोनों ही हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए गम्भीर चुनौती हैं। यह कहना अतिश्योक्ति न होगा कि ये दोनों एक ही बेहद खतरनाक सिक्के के दो पहलू हैं। हालांकि अभी तक छत्तीसगढ़ आतंकवादी घटनाओं से अछूता रहा है, फिर भी मुंबई घटना के बाद मेरी सरकार ने एक सी.ए.एफ बटालियन को कमांडो बटालियन में तब्दील करने का निर्णय लिया है, जो शहरी आतंकी हमलों की रोकथाम के उपाय करेगी। वैसे तो राज्य में नियमित तौर पर भी आतंकी गतिविधियों से संबंधित आसूचनाओं का संकलन विशेष शाखा से करने की व्यवस्था है लेकिन इसे और मजबूत करते हुए आतंकवाद संबंधी सूचनाओं के संकलन, विश्लेषण तथा अन्य राज्यों एवं केन्द्र के साथ आसूचना विनिमय के लिये 'एंटी टेररिस्ट कंट्रोल रूम' तथा 'एनालिसिस ग्रुप' की स्थापना भी राज्य मुख्यालय तथा सभी जिलों में की जाएगी। इसके साथ–साथ 'सबसिडिरी मल्टी एजेन्सी सेंटर' की बैठक अब सप्ताह में कम से कम एक बार आयोजित की जा रही है, जहां आतंकवाद तथा नक्सलवाद संबंधी आमसूचनाओं के संदर्भ में सेंट्रल इंटेलीजेंस तथा अन्य सुरक्षा संबंधी एजेन्सीज के बीच विचार–विमर्श किया जाता है और तद्नुसार कार्यवाही की जाती है।

9. मेरी सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सुरक्षा बलों की बढ़ोत्तरी के सार्थक प्रयास किए हैं। पुलिस बल में राज्य निर्माण के समय मात्र 22 हजार 592 पद थे, जिनमें 23 हजार 833 पदों की यानी 100 प्रतिशत से भी ज्यादा वृद्धि कर 46 हजार 425 पद कर दिया गया है। राज्य में कई नये थाने और चौकियां भी खोली गईं हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए निश्चय किया गया है कि राजधानी मुख्यालय तथा सभी जिलों में एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड का गठन किया जाएगा। सभी जिलों में गठित होने वाले ए.टी.एस. में कमांडो तैनात किये जाएंगे। राज्य में गठित एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड को सर्वसाधन संपन्न बनाया जाएगा तथा ए.टी.एस. कमांडो को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा।

10. मेरी सरकार का मानना है कि विगत वर्षों में छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के जो अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं, उनके कारण छत्तीसगढ़ को अनेक क्षेत्रों में देश का अव्वल तथा तेजी से विकासशील राज्य का गौरव मिला है। विकास की इस गति को और तेज करने के लिए राज्य के सभी क्षेत्रों में प्रगति दर्ज करनी होगी। आपको विदित ही है कि नक्सलवाद के कारण छत्तीसगढ़ तथा इसके सभी सीमावर्ती राज्य प्रभावित हैं। इस वजह से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की चुनौती हम सबके सामने हैं। मेरी सरकार ने विगत पांच वर्षों में इन अंचलों में आधारभूत सुविधाओं तथा सामाजिक–आर्थिक विकास के कार्य करते

हुए नक्सलवाद के शमन की दिशा में ठोस कदम उठाये हैं, जिसका प्रमाण इन क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव विगत वर्षों की तुलना में ज्यादा सुचारू और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो पाए। यहां की जनता ने भी बड़ी संख्या में मतदान करके बता दिया है कि वे नक्सलीवादी हिंसक तत्वों के बजाय लोकतंत्र को प्राथमिकता देते हैं।

11. वनांचलों में राष्ट्रविरोधी हिंसक तत्वों से मुकाबला कर रहे वीर अनुसूचित जनजातियों के शांति और जनजागरण अभियानों को मेरी सरकार का जो सहयोग मिलता रहा है, उसे सुदृढ़ करते हुए प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की जिम्मेदारी उठाना सरकार का कर्त्तव्य है। इसलिए मेरी सरकार शांति अभियान और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को जारी रखेगी। साथ ही स्थानीय निवासियों और सुरक्षाबलों का मनोबल बढ़ाने और उनकी हिफाजत के भरसक प्रयास भी किए जाएंगे।

12. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार गांव, खेती और किसान हैं। मेरी सरकार ने खेती और किसानों की स्थिति में सुधार का जो बड़ा अभियान छेड़ा था, उसकी वजह से दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कृषि क्षेत्र की उपलब्धि राष्ट्रीय औसत जो कि तीन प्रतिशत है, के मुकाबले 7 प्रतिशत से अधिक रही है।

13. विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के वर्तमान दौर में अनेक प्रदेशों में जहां बुनियादी सुविधाओं में कटौती की जा रही है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में मेरी सरकार ने खाद्यान्न सुरक्षा के लक्ष्य को अर्जित करने तथा किसानों एवं गरीबों को मंदी की मार से बचाने के लिए लगभग 2 हजार करोड़ रूपए जैसी बड़ी धन राशि का व्यय करने में संकोच नहीं किया किसानों का धान समर्थन मूल्य पर खरीदने की संपूर्ण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के जो उपाय विगत कार्यकाल में किए गए थे, उनसे किसान भाइयों के चेहरों पर मुस्कराहट आई है। मेरी सरकार ने नए कार्यकाल का सबसे पहला फैसला किसानों को धान खरीदी पर 270 रूपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने का फैसला लिया है, जिसमें केन्द्र सरकार का 50 रूपए प्रति क्विंटल का बोनस भी शामिल है । बोनस वितरण से राज्य शासन पर लगभग 880 करोड़ रूपए का वित्तीयभार पड़ने की संभावना है। इस तरह छत्तीसगढ़ किसानों को देश में सबसे ज्यादा बोनस देने वाला राज्य भी बन गया है।

14. मेरी सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में अब वह दिन लद गए जब किसानों को 15–16 प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण लेना पड़ता था। देश में अग्रणी पहल करते हुए छत्तीसगढ़ में कृषि ऋण की ब्याज दर को क्रमशः 3 प्रतिशत तक ला दिया गया है। कृशि ऋण सीमा भी तीन लाख रूपए से बढ़ाकर पांच लाख रूपए कर दी गई है। कृषि उपकरणों पर 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था भी कर दी गई है। खेती को लाभप्रद व्यवसाय बनाने की नीतियां और कार्यक्रम लागू करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है।

15. मेरी सरकार कृषि के साथ उद्यानिकी, फल–सब्जी एवं नगदी फसलों को भी प्रोत्साहित करेगी। मछली पालन, हार्टीकल्चर जैसे कार्यों के लिए लघु और सीमांत किसानों को सस्ती दर पर ऋण सुविधा दी जाएगी । गौ–पालन के माध्यम से डेयरी व्यवसाय करने वालों को भी सस्ती दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा।

16. किसानों को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार ने अनेक उपाय किए। विगत पांच वर्षों में आजादी के बाद के 50 वर्षों की तुलना में ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने में सफलता मिली । आप जानते ही हैं कि मेरी सरकार के विगत कार्यकाल के पूर्व राज्य में सिर्फ 72 हजार किसानों को पंप कनेक्शन मिले थे, जिनमें विगत पांच वर्षों में एक लाख 26 हजार नए कनेक्शन दिए गए हैं। मेरी सरकार ने राज्य में मोंगरा बैराज, सुतिया पाट, समोदा–निसदा, कोसारटेडा, खरखरा, मोंहदी पाट जैसी सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करते हुए 3 लाख 10 हजार हेक्टेयर रकबे में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की है । इस तरह हर खेत को पानी पहुंचाने के लक्ष्य की ओर अब और तेजी से बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा।

17. शुद्ध पेयजल का इंतजाम युद्ध स्तर पर करने की मेरी सरकार की पहल सफल रही है। 72 हजार 775 बसाहटों में से 71 हजार 714 बसाहटों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर दिया जाना इसका प्रमाण है। राष्ट्रीय मापदंड प्रति 250 व्यक्तियों के मुकाबले प्रति 88 व्यक्तियों पर एक हैण्ड–पम्प की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। नगरीय–निकायों की जल प्रदाय योजनाओं के लिए 30 प्रतिशत के स्थान पर 70 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था की गई, जो देश में सर्वाधिक है । इस तरह शहरों तथा गांवों में तेजी से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दर्ज हुआ है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत गांवों में 9 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है । इस प्रकार प्रदेश का सैनिटेशन कव्हरेज पूर्व के 8 प्रतिशत से बढ़कर अब लगभग 30 प्रतिशत हो गया है।

18. मेरी सरकार के लिए अच्छी अधोसंरचना का विकास सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। छत्तीसगढ़ को देश का पॉवर हब बनाने की दिशा में ठोस पहल की गई। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रगति पर है। विगत पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के माध्यम से बिजली का उत्पादन 1360 मेगावाट से बढ़ाकर 1924 कर दिया गया। बिजली कटौती और लो–वोल्टेज की समस्या का समाधान किया गया, जिसके कारण छत्तीसगढ़ को बिजली कटौती मुक्त राज्य होने का गौरव मिला। मेरी सरकार 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में संकल्पबद्ध है। विद्युत विकास का लाभ गरीबों तक पहुंचाने के लिए मेरी सरकार द्वारा करीब 9 लाख 50 हजार गरीब परिवारों को एकल–बत्ती कनेक्शन के माध्यम से निःशुल्क विद्युत प्रदाय किया जा रहा है।

19. सड़कों को विकास की जीवन–रेखा माना जाता है। विकास का लाभ राज्य के सभी वर्गों के लोगों को उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार ने राज्य में अच्छी सड़कों का जाल बिछाने का अभियान चलाया। विगत पांच वर्षों में लगभग 27 हजार 462 किलोमीटर सड़कों का डामरीकरण,नवीनीकरण तथा चौड़ीकरण किया जा चुका है। 476 बड़े,74 मध्यम पुल तथा 11 हजार से अधिक छोटी पुलिया बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 9417 कि.मी. सड़कें तथा 13106 पुल–पुलिया बनाई जा चुकी हैं, जिससे 3797 बसाहटों को जोड़ा गया है।

20. मेरी सरकार ने गांवों में पारंपरिक शिल्प जैसे रोजगार के वैकल्पिक साधन विकसित करने का संकल्प लिया है। बुनकर सहकारी समितियों पर बकाया चार करोड़ रूपए से ज्यादा का कर्ज माफ करके करीब आठ हजार परिवारों को नए सिरे से कारोबार करने की सुविधा दी गई है। खादी के बेहतर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीक के अम्बर चरखे और लूम के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। हाथकरघा, रेशम बुनकर तथा हस्तशिल्प से जुड़े कार्यों में पचास हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। मेरी सरकार इन तीनों क्षेत्रों में आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण की व्यवस्था बढ़ाएगी। स्थानीय जरूरतों और संसाधनों के आधार पर कुटीर उद्योगों की स्थापना और उत्पादों का विपणन नेटवर्क तैयार करने का काम भी प्राथमिकता से किया जाएगा ताकि ग्रामोद्योग ग्रामीणजनों की आमदनी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

21. छत्तीसगढ़ में बेहतर काम के लिए दूसरे राज्यों में जाने की परिपाटी रही है, जिसे पलायन का नाम भी दिया जाता है। मेरी सरकार ऐसे पलायन की पीड़ा एवं विवशता से मुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण करेगी। ग्रामीणों एवं खेतिहर मजदूरों के मन से अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना स्थाई समाधान के लिए पर्याप्त रोजगारमूलक कार्य किए जाएंगे।

22. मेरी सरकार ने असंगठित मजदूरों की समस्याओं को भी गहराई से समझा है और निदान के लिए ठोस प्रयास की रणनीति बना रही है, जिसके तहत असंगठित मजदूरों का पंजीयन कर उन्हें परिचय पत्र जारी किए जाएंगे। उनके परिवारजनों की निःशुल्क चिकित्सा तथा बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के उपाय किए जाएंगे। उनके कौशल उन्नयन के उपाय किए जाएंगे। असंगठित मजदूरों को व्यक्तिगत और परिवार बीमा का सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के उपाय भी किए जाएंगे।

23. मेरी सरकार ने गरीबों की जिंदगी की हर परेशानी को काफी करीब से महसूस किया है। गरीबी उन्मूलन के लिए बहुआयामी उपायों की जरूरत है। पूर्व अनुभवों के आधार पर स्व–सहायता समूहों को गरीबी उन्मूलन का महत्वपूर्ण माध्यम मानते हुए, ठोस कदम उठाने की रणनीति बनाई जा रही है। नवा अंजोर परियोजना को एक वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

24. देश में खाद्य सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों में मेरी सरकार का अग्रणी और अनुकरणीय योगदान दर्ज हुआ है। गरीब परिवारों के सामने सबसे बड़ी जरूरत दो–जून के भोजन का इंतजाम करने की होती है। मेरी सरकार ने विगत कार्यकाल में एक संकल्प लिया था कि छत्तीसगढ़ में कोई भी भूखे पेट सोने को विवश नहीं रहेगा। इस दिशा में अपना वचन निभाते हुए मेरी सरकार ने 37 लाख गरीब परिवारों को प्रति माह 35 किलो चावल 3 रूपए प्रति किलो की दर पर देने का कार्य किया था। इस योजना की पूरे देश ने दिल खोलकर तारीफ की है। इससे राज्य में जो उत्साह और राहत का वातावरण बना है, उसे मजबूत करने के लिए मेरी सरकार ने संकल्प लिया है कि राज्य के अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को मात्र एक रूपए किलो में चावल दिया जाएगा और शेष सभी गरीबों को मात्र दो रूपए किलो की दर से चावल दिया जाएगा।

25. छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति बहुल और दूरस्थ अंचलों में नमक जैसी अनिवार्य वस्तु का अभाव दूर करने के लिए मेरी सरकार ने 25 पैसे प्रति किलो में जो आयोडाइज्ड नमक देने की योजना शुरू की थी, वह एक तरह शोषण से मुक्ति और सामाजिक जागरण का प्रतीक बन गई है। अब मेरी सरकार राज्य के सभी गरीब परिवारों को प्रति माह दो किलो आयोडाइज्ड नमक निःशुल्क प्रदान करना चाहती है जो स्वास्थ्य के प्रति चेतना का माध्यम भी बनेगा।

26. मेरी सरकार राज्य की लगभग 45 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आबादी के दशकों से थमे विकास को गति देने की कारगर रणनीति बनाने में सफल रही है। इन वर्गो के रहने के स्थानों में बुनियादी अधोसंरचना के साथ ही सामाजिक अधोसंरचना का विकास सबसे बड़ी चुनौती रही है, जिसके लिए अन्य नियमित प्रशासनिक कार्यों के अलावा तीन अलग विकास प्राधिकरण बनाकर सुनिश्चित की गई प्रगति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के समस्त आवासहीन परिवारों को नए आवास उपलब्ध कराने की देश में एक अभिनव पहल मेरी सरकार ने की थी, जिसके अंतर्गत लगभग 28 करोड़ रूपए की लागत से सात हजार 926 आवास बनाकर दिए जा रहे हैं। ''अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006'' के अंर्तगत पात्र सर्वाधिक वनवासियों को उनकी काबिज भूमि का अधिकार पत्र देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। अभी तक एक लाख से अधिक लोगों को अधिकार पत्र दिए जा चुके हैं।

27. अनुसूचित अंचलों में शिक्षा को बेहतरी का माध्यम बनाने के लिए आश्रम शालाओं और छात्रावासों का जाल बिछाया गया है। आश्रम शालाओं की संख्या 516 से बढ़कर 1024 हो गई है, वहीं 556 नए छात्रावास स्थापित किए गए हैं। इन छात्रावास में एक लाख 40 हजार से ज्यादा छात्र–छात्राएं अध्ययनरत हैं। मेरी सरकार अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्र–छात्राओं को बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ व्यावसायिक परीक्षाओं और रोजगार के लिए तैयार करने के प्रयास जारी रखेगी।

28. मेरी सरकार ने वनोपज के कारोबार का ज्यादा से ज्यादा लाभ वनवासी भाई–बहनों को देने की पहल को भी एक नए शिखर तक पहुंचाया है। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 450 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ा कर 600 रूपए प्रति मानक बोरा का संग्रहण पारिश्रमिक दिया गया है। इसी तरह साल–बीज संग्रहण की दर भी 350 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर एक हजार रूपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। विगत वर्ष तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 120 करोड़ रूपयों का प्रोत्साहन पारिश्रमिक दिया गया। लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश का अव्वल राज्य बन गया है। इस तरह के प्रयास जारी रखकर वनवासियों की आमदनी में बढ़ोत्तरी का अभियान जारी रखा जाएगा। वनोपज के कारोबार में प्रमुख भागीदारी निभाने वाली विभिन्न स्तरों की सहकारी समितियों में निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराए गए हैं। इस तरह मेरी सरकार ने दूरस्थ अंचलों के अंतिम स्तर तक लोकतंत्र की मजबूती के कदम उठाए हैं, जो देश में अपनी तरह का अभिनव प्रयास है।

29. राज्य में आजीविका के लिए बांस पर निर्भर दस्तकारों को रियायती दर पर बांस उपलब्ध कराया जाएगा। बांस का उत्पादन बढ़ाने के उपायों के साथ ही 14 बांस प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है और 20 प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। वनौषधियों का पेटेंट कराते हुए इनके प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। अराष्ट्रीयकृत लघुवनोपज जैसे इमली, लाख, माहुल पत्ता, शहद, महुआ–बीज तथा चिरौंजी आदि के संग्रहण, प्रसंस्करण तथा वितरण की व्यवस्था की जा रही है। 25 गांवों को आयुर्वेद ग्राम के रूप में विकसित कर वहां वनौषधि रोपण तथा प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। 8 जिलों वनौषधि उद्यान और प्रदर्शन प्रक्षेत्रों की स्थापना की जाएगी, वही धमतरी जिले में हर्बल मंडी बनाई जाएगी।

30. राज्य में जिस गति से औद्योगिक विकास की संभावनाएं बढ़ रही हैं, उसी गति से स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षित–प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने की चुनौती का सामना करने हेतु मेरी सरकार विशेष रणनीति बनाएगी।

31. मेरी सरकार ने विगत पांच वर्षों में महिला सशक्तीकरण के अनेक व्यावहारिक उपाय किए हैं। पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के नाम से भूमि खरीदने पर पंजीयन शुल्क में दो प्रतिशत की छूट दी जा रही है। निर्धन कन्या विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 10 हजार से अधिक बालिकाओं को विवाह हेतु आर्थिक मदद दी गई है। हाईस्कूल में पढ़ने वाली सभी वर्गों की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय की योजना का लाभ एक लाख 50 हजार से अधिक छात्राओं को मिला है। एक लाख से अधिक छात्राओं को निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा का लाभ मिला है। 50 लाख से अधिक स्कूली छात्र –छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की गई हैं। आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित पूरक–पोषण आहार योजनाओं से 32 लाख से अधिक महिलाओं तथा बच्चों को लाभ मिल रहा है। नारी शक्ति का सम्मान करते हुए उनके हित में नई योजनाएं प्रारम्भ करने के लिए भी मेरी सरकार संकल्पबद्ध है। इस दिषा में नई पहल करते हुए अब महिलाओं के नाम पर नए गैस कनेक्शन

लेने में 100 रूपए की सबसिडी प्रदान की जाएगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निःशुल्क सायकल प्रदान करने की योजना लागू की जाएगी। बुजुर्गों के सम्मान और निःशक्तजनों के पुनर्वास पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा।

32. प्रशासन तंत्र की जवाबदेही और गतिशीलता को और बढ़ाया जाएगा। मेरी सरकार ने छत्तीसगढ़ में जो बेहतर कार्य संस्कृति और बेहतर कार्य का वातावरण बनाने की पहल की थी, उसके परिणामस्वरूप विगत कार्यकाल में न सिर्फ हजारों युवाओं को शासकीय तथा अर्धशासकीय विभागों में नौकरी मिली, बल्कि दैनिक वेतनभोगी के रूप में बरसों से कार्य कर रहे करीब 20 हजार व्यक्तियों को नियमितीकरण का लाभ भी दिया गया। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक संवेदनशीलता की एक मिसाल हजारों की संख्या में प्रदान की गई अनुकम्पा नियुक्ति भी है। राज्य के लाखों अधिकारियों को छठवां वेतन आयोग के तहत नया वेतनमान देने की घोषणा की गई। शिक्षाकर्मियों को संपूर्ण शिक्षक का सम्मान दिलाने हेतु किए गए प्रयासों को मेरी सरकार और आगे बढ़ाएगी। उन्हें समयबद्ध पदोन्नति का लाभ दिया जा रहा है। जरूरत के अनुसार उनके रिक्त पदों पर संविलियन की कार्यवाही की जा रही है।

33. मेरी सरकार ने स्थानीय निकायों को अधिकाधिक स्वायत्ता देने की रणनीति अपनाई है। ताकि इन संस्थाओं में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत फैसले हों। इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और स्थानीय स्तर पर जनता की जरूरतों का सही आकलन कर ये संस्थायें विकास कार्यों में अहम योगदान दे सकें। सभी स्थानीय–निकायों में समन्वित विकास योजना बनाकर उनका क्रियान्वयन किया जाएगा।

34. मेरी सरकार ने जनस्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार करके न सिर्फ अनेक बीमारियों पर नियंत्रण करने में सफलता पाई है, अपितु अनेक स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार भी किया है। शिशु मृत्यु दर 79 प्रति हजार से घटकर 61 प्रति हजार रह गई है। मातृ मृत्यु दर 407 प्रति लाख से घटकर 379 प्रति लाख जीवित जन्म रह गई है, विगत पांच वर्षों में पोलियो का एक भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। कुष्ठ प्रभावी दर 7.72 से घटकर 2.38 प्रतिशत रह गई है। मेरी सरकार इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए राज्य में सबके अच्छे स्वास्थ्य का लक्ष्य अर्जित करने को तत्पर है। 18 हजार 322 गांवों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों का गठन कर उन्हें करीब 61 करोड़ रूपए की राशि वितरित कर इस दिशा में ठोस पहल की जा चुकी है। गरीबी रेखा के नीचे की आबादी को निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना को छह जिलों से प्रारम्भ किया गया है, जिसका भविष्य में विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक बीपीएल परिवार को एक साल में तीस हजार रूपए तक की स्वास्थ्य सुविधा सरकारी तथा चिन्हांकित अस्पतालों में मिल सकेगी। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न स्तरों पर रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही शीघ्र की जाएगी। राज्य में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की मदद से नए मेडिकल कॉलेज खोलने की पहल भी की जा रही है। अनुसूचित जनजाति और दूरस्थ अंचलों में मोबाइल स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोत्तरी की जाएगी। जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार द्वारा लागू की गई अभिनव योजनाओं की एक मिसाल

'मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना भी है, जिसके अंतर्गत बीते छह माह में ही अनेक जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा का लाभ दिया गया है। ऐसी योजनाओं को जारी रखा जाएगा।

35. मेरी सरकार ने राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों के स्थानीय स्तर पर ही वेल्यू–एडीशन से औद्योगिक क्रांति की रणनीति बनाई है। इसके लिए जो नई उद्योग नीति बनाई जाएगी, उसमें पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय विकास को भी प्राथमिकता दी जाएगी। नए उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की शर्त और अधिक प्रमुखता से रहेगी। लघु, कुटीर, परम्परागत तथा गैरपरम्परागत उद्योगों के माध्यम से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के भरपूर अवसर प्रदान किए जाएंगे। औद्योगिकीकरण के इस दौर में क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ को देश का पॉवर–हब बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों की गति और तेज की जाएगी । नए विद्युतगृहों की स्थापना निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करने के भरसक प्रयास किए जाएंगे। परम्परागत और गैरपरम्परागत ऊर्जा के विकास से राज्य के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य पूरा किया जाएगा।

36. राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित सुधार कार्यक्रम के तहत मेरी सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को पांच शासकीय कंपनियों में पुनर्गठित किया है। इससे विद्युत उत्पादन, पारेषण, विपणन, वितरण जैसी गतिविधियों को ज्यादा व्यावसायिक ढंग से संचालित करने का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं कंपनियों की विशिष्ट जावाबदेही निर्धारित होने से विद्युत के माध्यम से किए जाने वाले विकास और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सकेगा। मेरी सरकार ने आश्वस्त किया है कि इस पुनर्गठन से आम उपभेक्ता तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा।

37. छत्तीसगढ़ में बुनियादी अधोसंरचना के विकास को राज्य आम आदमी के विकास का प्रमुख माध्यम बनाया जा रहा है। अनेक स्थानों पर सुविधायुक्त स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। खेल मैदानों का विकास किया जा रहा है। खेलकूद प्रशिक्षण की उच्चस्तरीय सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। राज्य में स्थापित किए गए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेल गतिविधियां प्रारम्भ हो जाने से राज्य की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।

38. मेरी सरकार की राज्य के विकास की परिकल्पना में परम्परागत मूल्यों और संस्कृति के संरक्षण का केन्द्रीय स्थान है। छत्तीसगढ़ी को राज भाषा का दर्जा दिलाने के साथ अब इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का गौरव प्रदान करने के लिए सुनियोजित प्रयास किए जाएंगे। विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए जनजाति संग्रहालयों की स्थापना की जाएगी। राज्य के पुरातात्विक, पौराणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, प्राकृतिक महत्व के स्थलों को सुविधाजनक पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा।

39. मेरी सरकार ने छत्तीसगढ़ को, यहां के निवासियों को सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया में प्रतिष्ठा दिलाने का सपना देखा है। स्थानीय साधनों और अवसरों के भरपूर उपयोग की क्षमता विकसित करने के साथ ही यहां वैश्विक स्तर की सुविधाएं भी सबको उपलब्ध हो, इसका पर्याप्त ध्यान रखा जाएगा।

40. आने वाले समय में छत्तीसगढ़ न सिर्फ अच्छी अधोसंरचना और संवेदनशील प्रशासन के लिए जाना जाएगा, बल्कि श्रेष्ठतम इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन (ई–गवरॅनेन्स) के लिए भी जाना जाएगा। मेरी सरकार छत्तीसगढ़ को हर मामले में सर्वश्रेष्ठ और देश का अव्वल राज्य बनाने के लिए कृतसंकल्प है। जिसमें आम आदमी की आवाज का बोल–बाला होगा, जहां आम आदमी की अच्छा सबसे महत्वपूर्ण होगी और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने की व्यवस्था बना ली जाएगी । यह नया दौर शांति, समरसता, विकास और खुशहाली के नए कीर्तिमान गढ़ेगा। आम जनता और उनके प्रतिनिधि के रूप में आप सबके सहायोग से ही यह लक्ष्य हासिल किया जाएगा।

नए वर्ष की शुभकामनाओं सहित।

जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़